



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 379]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सं. 65/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 592(अ)।—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा;

1. (1) इन विनियमों को कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2010, (एतश्मिन् पश्चात् जिसे प्रधान विनियम से संदर्भित किया गया है) में,-

(1) विनियम 13 में, उपविनियम (1) में,-

(i) प्रथम परंतुक को निरसित कर दिया जाएगा।

(ii) दूसरे परंतुक में शब्द “और आगे” को निरसित कर दिया जाएगा।

(iii) तीसरे परंतुक में, शब्द “बशर्ते भी कि” के स्थान पर शब्द “बशर्ते और भी कि” प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. प्रधान विनियमावली के नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“13 क. नियम 13 के अंतर्गत पंजीकरण के प्रतिसंहरण की प्रक्रिया-

(1) आयुक्त सीमाशुल्क प्राधिकृत कूरियर को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें वह आधार बताया जाएगा जिसके आधार पर पंजीकरण को वापस लिये जाने का प्रस्ताव किया गया है और प्राधिकृत कूरियर के लिये यह जरूरी बताया जायेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो कि इस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, जो कि 45 दिन से कम न हो, उपायुक्त सीमाशुल्क या उसके द्वारा नामित सहायक आयुक्त सीमाशुल्क को अपने बचाव में लिखित विवरण प्रस्तुत करे और उक्त विवरण में यह स्पष्ट किया जायेगा कि क्या प्राधिकृत कूरियर उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो के समक्ष सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहता है या नहीं।

(2) सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, प्राधिकृत कूरियर से ऐसे लिखित विवरण प्राप्त होने के पश्चात्, या जहां कि ऐसा विवरण उपनियम 1 में संदर्भित नोटिस में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता है तो उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, आयुक्त सीमाशुल्क के निर्देश पर स्थगन आदेश या जांच की तारीख, जैसी भी स्थिति हो के 3 महीने के भीतर उन आधारों की जांच करेगा जोकि प्राधिकृत कूरियर को स्वीकार नहीं है।

(3) सही स्थिति का पता लगाने के लिये, आयुक्त सीमाशुल्क या उपायुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य ग्रहण करेगा जो कि सुसंगत हो और जांच की कार्यवाही में सारवान सिद्ध हो और जो प्रक्रिया को आधार प्रदान करते हों और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकता है जो कि प्राधिकृत कूरियर के पक्ष में या उसके खिलाफ कोई साक्ष्य दे रहा हो।

(4) प्राधिकृत कूरियर के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसी प्रक्रिया को आधार प्रदान करने वाले समर्थन में प्रश्नगत किये जाने वाले व्यक्तियों से प्रतिप्रश्न पूछ सकता है और जहां उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे किसी व्यक्ति से इस आधार पर पूछे जाने से मना कर सकता है कि इस प्रकार का साक्ष्य सुसंगत अथवा सारवान नहीं है तो वह इसके कारणों को भी लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(5) जांच के समापन पर उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो जांच की अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और अपने निष्कर्षों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(6) आयुक्त सीमाशुल्क प्राधिकृत कूरियर को उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की रिपोर्ट की एक प्रति देगा और प्राधिकृत कूरियर के लिये जरूरी करेगा कि वह एक विनिर्दिष्ट अवधि, जो कि 60 दिन से कम न हो, अपना अभ्यावेदन दे कि वह उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के खिलाफ कुछ कहना चाहता है या नहीं।

(7) आयुक्त सीमाशुल्क जांच की रिपोर्ट और उस पर प्राधिकृत कूरियर द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

टिप्पणी :— प्रधान अधिसूचना सं. 36/2010- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010 को सा.का.नि. 385 (अ) दिनांक 5 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 26/2011- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 290 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2011 के तहत, के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2012

No. 65/2012-Customs (N.T.)

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2012.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, (hereinafter referred to as the principal regulations),-
 - (1) in regulation 13, in sub-regulation (1),-
 - (i) the first proviso shall be omitted;
 - (ii) in the second proviso, the words "further" shall be omitted;
 - (iii) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted.
 - (2) after regulation 13 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"13A. Procedure for revoking registration under regulation 13.-"

- (1) The Commissioner of Customs shall issue a notice in writing to the Authorised Courier stating the grounds on which it is proposed to revoke the registration and requiring the said Authorised Courier to submit, within such time as may be specified in the notice, not being less than forty-five days, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs nominated by him, a written statement of defence and also to specify in the said statement whether the Authorised Courier desires to be heard in person by the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.

- (2) The Commissioner of Customs may, on receipt of the written statement from the Authorised Courier, or where no such statement has been received within the time-limit specified in the notice referred to in sub-regulation (1), direct the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to inquire within a period of three months, from the order of suspension or from the date of initiation of enquiry, as the case may be, into the grounds which are not admitted by the Authorised Courier.
- (3) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall, in the course of inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material to the inquiry in regard to the grounds forming the basis of the proceedings, and he may also put any question to any person tendering evidence for or against the Authorised Courier, for the purpose of ascertaining the correct position.
- (4) The Authorised Courier shall be entitled to cross-examine the persons examined in support of the grounds forming the basis of the proceedings, and where the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, declines to examine any person on the grounds that his evidence is not relevant or material, he shall record his reasons in writing for so doing.
- (5) At the conclusion of the inquiry, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall prepare a report of the inquiry recording his findings.
- (6) The Commissioner of Customs shall furnish to the Authorised Courier a copy of the report of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, and shall require the Authorised Courier to submit, within the specified period not being less than sixty days, any representation that he may wish to make against the findings of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.
- (7) The Commissioner of Customs shall, after considering the report of the inquiry and the representation thereon, if any, made by the Authorised Courier, pass such orders as he deems fit.”

[F. No. 450/54/2008-Cus.-IV]

VIKAS, Under Secy.

Note :—The principal Notification No. 36/ 2010 -Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 5th May, 2010 vide G.S.R.385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended by notification No. 26/2011-Customs (N.T.),dated the 1st April, 2011 vide number G.S.R. 290(E), dated the 1st April, 2011.